योजनाओं और नीतियों का जमीन

ऐसे खास मानकों की जरूरत होती है, जिससे पता चले कि विभिन्न सरकारों द्वारा शुरू की गई और चलाई जा रही योजनाओं और नीतियों का जमीन पर कैसा और कितना प्रभाव पड़ रहा है, उससे आम नागरिकों के जीवन में किस तरह के और कितने बदलाव आ रहे हैं।

मर्नाज शाह।।

नीति आयोग की ओर से जारी की गई पहली मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (एमपीआई) रिपोर्ट जहां अलग–अलग राज्यों के हालात का ब्योरा देती है, वहीं नीति निर्धारकों के लिए एक नई और बेहतर कसौटी भी मुहैया कराती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, अगर 51.9 फीसदी गरीब आबादी के साथ बिहार गरीब राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है और 0.71 फीसदी गरीब आबादी के साथ केरल सबसे नीचे तो अपने आप में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

ऊपर और नीचे के कुछ और राज्य देखें तो अपेक्षा के अनुरूप ही बिहार के साथ झारखंड, यूपी और मध्य प्रदेश खड़े मिलते हैं, जबकि केरल के साथ गोवा, सिक्किम और तमिलनाडु। साफ है कि आम लोगों तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने और उनका जीवन स्तर ऊंचा करने के मामले में कुछ राज्यों ने उल्लेखनीय सफलता पाई है, जबकि कुछ अन्य राज्य इस मामले में बहुत पीछे हैं। मगर इसका ठीक–ठीक अंदाजा हमें पूंजी निवेश या प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों से नहीं मिलता। इसीलिए ऐसे खास मानकों की जरूरत होती है, जिससे पता चले कि विभिन्न सरकारों द्वारा शुरू की गई और चलाई जा रही योजनाओं और नीतियों का जमीन पर कैसा और कितना प्रभाव पड़ रहा है, उससे आम नागरिकों के जीवन में किस तरह के और कितने बदलाव आ रहे हैं। इस संदर्भ में नीति आयोग की यह मल्टी डाइमेंशनल इंडेक्स रिपोर्ट अहम हो जाती है। हालांकि इसके लिए जरूरी आंकड़े नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस) की 2015–16 की रिपोर्ट से लिए गए हैं और इस लिहाज से ये पांच साल पहले के हालात का ब्योरा पेश करते हैं। लेकिन इसकी असल अहमियत इसकी मेथडॉलजी में निहित है। एमपीआई समान महत्व के तीन कारकों– स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर– के आधार पर स्थिति का आकलन करता है और इसके लिए 12 इंडिकेटर्स का उपयोग हुआ है। यह महज गरीबी रेखा के आधार पर गरीबी नापने के पारंपरिक तरीके से निश्चित रूप से अलग है। यह 2015 में 193 देशों द्वारा अपनाए गए सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल (एसडीजी) के वैश्विक फ्रेमवर्क के अनुरूप है। जहां तक पिछले पांच साल के दौरान हुई प्रगति का सवाल है तो जैसा कि नीति आयोग का कहना है, एनएफएचएस के ताजा सर्वे के सभी आंकड़े जारी होने के बाद इसके आधार पर बनाई जाने वाली दूसरी एमपीआई रिपोर्ट में वह भी कवर हो जाएगी, लेकिन असली चुनौती केंद्र और राज्य सरकारों के लिए यह है कि वे अपनी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को नीति आयोग द्वारा मुहैया करवाई गई इस कसौटी पर कसते हुए आगे बढ़ें। चाहे देश में पूंजी निवेश बढ़ाने की बात हो या जीडीपी की रफ्तार तेज करने की, इन सबका आखिरी हासिल तो यही होता है कि उससे देश के सामान्य लोगों के जीवन तक कितनी सुविधाएं पहुंचीं, उसमें कितनी क्वॉलिटी आ सकी। इसीलिए यह भी जरूरी है कि सरकार की उपलब्धियों को ऐसे मानकों पर कसने का सिलसिला किसी वजह से थमने न दिया जाए।

धार्मिक ज्ञान

अशोक वोहरा।

धार्मिक ज्ञान वह है जो एक हठधर्मिता पर आधारित है, एक और अधिक राशन या वैज्ञानिक चर्चा के बिना एक स्वीकृत विश्वास पर। धार्मिक ज्ञान में व्यक्ति और उसके चारों ओर व्याप्त वास्तविकता की कल्पना की जाती है, जो किसी उच्चतर, एक दिव्यता से संबंधित है। यह लोगों को ईमानदारी से किसी ऐसी चीज पर विश्वास करने की अनुमति देता है, जिसे साबित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के ज्ञान की एक और विशेषता यह है कि यह लिखित या मौखिक परंपरा पर आधारित है, और जितनी जल्दी या बाद में, यह आदर्श बन जाता है, अर्थात, यह नियम, मानदंड और मूल्य पैदा करता है जो बिना किसी प्रश्न के पूरा होना चाहिए। यह उन अनुष्ठानों और कार्यों को भी उत्पन्न करता है जो एक पवित्र अस्तित्व का उल्लेख करते हैं।

संपादकीय

कैश ट्रांसफर हो

कायदे से घरेलू मांग बढ़ाने के लिए सरकार को दो नीतियों पर विचार करना चाहिए। एक यह कि तमाम कल्याणकारी परियोजनाएं समाप्त कर जनता को सीधे नकद वितरण करे। इन कल्याणकारी योजनाओं में कार्यरत सरकारी कर्मी मूल रूप से आढ़ती हैं। जिस प्रकार सरकार मंडियों में किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ना चाहती है, उसी प्रकार लाभार्थी को सीधे रिजर्व बैंक से जोड़ना चाहिए। इनके बीच में आढ़त की बचत करनी चाहिए, जिससे आम आदमी के हाथ में क्रयशक्ति ज्यादा आए और बाजार में मांग बने। दूसरी बात यह कि उद्यमियों, एक्टरों, सरकारी कर्मियों और नेताओं द्वारा जो रकम कानूनी या गैर–कानूनी तरीकों से विदेश भेजी जा रही है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। एशियन डिवेलपमेंट बैंक द्वारा जो बताया गया कि वर्तमान डिमांड मुख्यतरू प्रशासन और रक्षा के क्षेत्रों में है, यह वास्तव में संकट का संकेत है। प्रशासनिक खर्च में सरकारी कर्मियों के वेतन और सरकारी ठेकों में रिसाव सम्मलित होता है। रिजर्व बैंक ने भी इस संभावना के प्रति संकेत किया है। कहा है कि निर्यात की मांग से भारतीय अर्थव्यवस्था के चलने की संभावना है। ठीक वैसे ही, जैसे घर का बच्चा रेस्तरां में मांग बढ़ा सकता है। तब देश की पूंजी अपने देश में रहेगी, यहीं मांग उत्पन्न होगी और हमारी अर्थव्यवस्था का चक्का बिना सस्ते लोन के ही चल निकलेगा।

ऐसी चढ़ाई को तेज विकास नहीं बल्कि तेज क्षतिपूर्ति कहना चाहिए। ऐसा भी कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बीमारी से सबसे तेजी से निकल रही है। लेकिन बीमारी से निकलने वाले को दौड़ में अव्वल नहीं कहा जा सकता।

आपूर्ति पर ध्यान

भरत झुनझुनवाला।।

भारत विश्व की सबसे तेज चलने वाली अर्थव्यवस्था बन चुकी है, लेकिन चुनौतियां बरकरार हैं। हमारी परिस्थिति उस व्यक्ति जैसी है, जो पहाड़ से नीचे गिरने के बाद फिर से पहाड़ पर सबसे तेज चढ़ रहा होता है। ऐसी चढ़ाई को तेज विकास नहीं बल्कि तेज क्षतिपूर्ति कहना चाहिए। ऐसा भी कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बीमारी से सबसे तेजी से निकल रही है। लेकिन बीमारी से निकलने वाले को दौड़ में अव्वल नहीं कहा जा सकता। तमाम आकलनों के अनुसार, इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग नहीं है। रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि डिमांड कमजोर है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली चौंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि घरेलू खपत को बढ़ाना जरूरी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी ने कहा है कि 2019–20 में जीडीपी में 6.2 प्रतिशत की गिरावट आई, लेकिन खपत में 7.2 प्रतिशत की। यानी फैक्ट्रियां माल बना कर स्टॉक कर रही हैं। मांग का अभाव है। एशियन डिवेलपमेंट बैंक ने भी कहा है कि बाजार में मांग असल में सरकारी प्रशासन और रक्षा के क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही है। इनके अनुसार भी जनता की खपत कमजोर है।

इन आकलनों के विपरीत यह भी सही है कि कृषि में उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन कृषि

उत्पादन बढ़ने और कृषि उत्पादन की खपत होने में मौलिक अंतर है। कृषि उत्पादन का निर्यात अधिक हो रहा दिखता है। बिजली की खपत में वृद्धि तेल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण हो सकती है। लोगों ने डीजल जनरेटर चलाना और निजी कार में सफर करना कम कर दिया है। जीएसटी की वसूली बढ़ रही है। लेकिन यह बड़े उद्योगों में उत्पादन बढ़ने के कारण दिखती है। छोटे उद्योगों के उत्पादन में गिरावट और बड़े उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि बराबर होने से कुल उत्पादन बराबर है, लेकिन जीएसटी की वसूली बढ़ रही है। जैसे– हैंडलूम के स्थान पर पॉवरलूम से उत्पादन किया जाए तो बिजली की खपत और जीएसटी दोनों बढ़ जाती हैं। हालांकि उत्पादन और खपत उतनी ही रहती है। घरेलू मांग के अभाव में आर्थिक विकास का गति पकड़ना कठिन ही दिखता है। यह वैसा ही है, जैसे घर की रोटी के अभाव में स्पोर्ट्सवुमन का बढ़ना कठिन होता है।

इस परिस्थिति में सरकार की नीति है कि उत्पादन को और सस्ता बनाया जाए। रिजर्व बैंक ने तरल मुद्रा नीति लागू कर रखी है। रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों को आसान दर पर पर्याप्त लोन दिया जा रहा है, जिससे कि ब्याज दर कम रहे और वे उद्योगों को लोन दे सकें। सोच यह है कि इससे उद्योगों की उत्पादन लागत कम आएगी, बाजार में माल के दाम गिरेंगे, सस्ते माल के लालच में लोग खरीदारी करेंगे। जैसे कि सेल लगी हो तो लोग दुकानों पर टूट पड़ते हैं। सरकार ने बड़ी कंपनियों पर आयकर में भी कटौती की है और उत्पादन से लिंक करके प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिससे कंपनियों का उत्पादन बढ़े। जैसे कपड़ा फैक्ट्री को यदि लोन सस्ता मिले, उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि मिले और आयकर कम देना पड़े तो वह कपड़े को 25 रुपये प्रति मीटर के स्थान पर 22 रुपये प्रति मीटर में बेचने को तत्पर हो सकती है। लेकिन 22 रुपये प्रति मीटर कपड़े खरीदने वाले खरीदार उपस्थित न हों तो बात नहीं बनेगी। जैसे तीन वर्ष पहले पालनपुर के किसानों को 5 रुपये प्रति किलो में भी आलू के ग्राहक नहीं मिले थे और उन्होंने सड़क पर आलू डंप कर दिए थे। यही इस समय चुनौती है। खरीदार नदारद है।

सूडोकु नवताल-5321

8		4	3	9	7	5		6
3					2			
		7	6	5				4
9	6		5			1		7
5		1	4		9	8		2
4		8					5	3
2				6	1	4		
			7					8
7		9	8	3	5	6		1

सूडोकु नवताल -5320 का हल

7	8	4	9	5	2	6	1	3
9	6	2	4	3	1	8	5	7
1	3	5	7	8	6	2	4	9
4	2	3	8	1	5	9	7	8
8	5	9	2	4	7	1	3	6
6	7	1	3	9	8	4	2	5
3	1	7	8	6	4	5	9	2
5	9	6	1	2	3	7	8	4
2	4	8	5	7	9	3	6	1

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

अपना ब्लॉग

सप्लाई बढ़ाने की नीति को अपनाया

मोहन। इस जकड़न को तोड़ने के लिए दूसरी वैकल्पिक नीति पर विचार करना जरूरी है। सप्लाई के स्थान पर डिमांड को बढ़ाया जाए। जैसे बाजार में मास्क की डिमांड बढ़ती है तो मास्क बनाने की नई फैक्टिरियां स्वतः लग जाती हैं, वे सस्ते लोन को नहीं देखती हैं। डिमांड बढ़ाकर आर्थिक विकास हासिल करना ठोस परिणाम देता है। संभव है कि सरकारी कर्मियों और नेताओं द्वारा रकम को विदेशों में भेजा जा रहा हो। मान लीजिए, किसी सरकारी कर्मी या नेता ने भारत से 100 करोड़ रुपये की राशि दूसरे देश को भेज दी। वहां मकान बनाया। उस मकान को बनाने में भारत से ऐल्युमिनियम का निर्यात हुआ। ऐसे में हमारी ही राशि से मांग विदेश में पैदा होती है, न कि अपने देश में। मास्क की डिमांड होती है तो जैसे–तैसे उत्पादक मास्क का उत्पादन करके बाजार में उपलब्ध करा ही देते हैं। लेकिन सरकार ने सप्लाई बढ़ाने की नीति को अपनाया है। इस नीति में माल की बिक्री अनिश्चित रहता है।